भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3947
जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

किसानों को आसान ऋण के लिए योजनाएं

3947. डॉ. राजकुमार सांगवान:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बागपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश में किसानों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले युवाओं को आसान ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए कोई विशेष वित्तीय योजना शुरु की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान बागपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश में उक्त श्रेणियों को प्रदान किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने बागपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश में ऋण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों में स्थानीय स्तर पर कोई विशेष अभियान, हेल्पलाइन या ऋण परामर्श केन्द्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सरकार ने किसानों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार वाले युवाओं को ऋण प्रवाह की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।

(ख): उत्तर प्रदेश और बागपत जिलों में सरकार की उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत/संवितरित ऋणों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): सरकार ने विभिन्न ऋण सुविधाओं को सरल, पारदर्शी और दक्ष बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित शामिल हैं:-

- सभी पात्र किसानों को केसीसी प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केसीसी संतृप्ति अभियान आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) में लगे सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लाभों तक पहुँच बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी जिला स्तरीय साप्ताहिक शिविर भी आयोजित किए गए थे।
- वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल), वित्तीय साक्षरता शिविरों (एफएलसी) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं जिनकी स्थापना क्रमश भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक देश भर में जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रचार करने के लिए प्रत्येक वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) का भी आयोजन करता है।
- बैंकिंग प्रतिनिधि (बीसी) बैंकिंग सेवा वितरण प्रणाली में अंतिम छोर तक संपर्क का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत पात्र लोगों को भी नामांकित किया जाता है।
- डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (डीबीयू): डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और उपयोगकर्त्ता के अनुकूल बनाने के लिये देश के हर कोने में डिजिटल बैंकिंग का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डिजिटल बैंकिंग इकाइयां – डीबीयू) की स्थापना की गई है। ये इकाइयां बचत बैंक खाते खोलने, पासबुक मुद्रण, निधियों का अंतरण, ऋण आवेदन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं।
- इसके अलावा, उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से पात्र लाभार्थियों को त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए जन समर्थ पोर्टल, पीएसबी लोन इन 59 मिनट, पीएम स्वनिधि पोर्टल आदि जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए हैं।

*****

अनुबंध- I

"किसानों को आसान ऋण योजनाएँ" के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को उत्तर के लिए देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3947, के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) - वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को सक्रिय खाते

(खातों की संख्या '000 और राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	उत्तर प्रदेश		बागपत	
	खाते	बक़ाया धनराशि	खाते	बकाया राशि
2020-21	11,281	1,18,066	डेटा उपलब्ध नहीं है	
2021-22	10,471	1,23,034	101	1376.83
2022-23	10,705	1,28,115	112	1572.19
2023-24	10,917	1,38,621	115	1689.27
2024-25	10,956	1,41,375	117	1758.35

स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एसएलबीसी उत्तर प्रदेश

वर्तमान वर्ष केसीसी ऑपरेटिव डेटा अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	उत्तर प्रदेश		बागपत	
	खाते	स्वीकृत राशि	खाते	स्वीकृत राशि
2020-21	47,38,452	29,231.35	23,557	131.00
2021-22	57,87,982	33,663.73	33,017	193.25
2022-23	68,08,721	48,194.90	48,881	294.36
2023-24	76,79,518	59,506.73	53,734	396.92
2024-25	59,24,230	58,837.78	36,299	375.67
2025-26*	6,39,913	8602.84	4721	70.59

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

*: जून *2025* तक के आंकड़े

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	उत्तर प्रदेश		बागपत	
	खाते	स्वीकृत राशि	खाते	स्वीकृत राशि
2020-21	12,276	395.90	91	3.37
2021-22	13,019	426.01	142	4.77
2022-23	19,660	688.06	106	3.90
2023-24	19,551	774.82	91	4.11
2024-25	7,442	340.56	34	1.78

स्रोत: केवीआईसी पोर्टल

पीएम विश्वकर्मा

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	उत्तर प्रदेश		बागपत	
	खाते	स्वीकृत राशि	खाते	स्वीकृत राशि
2024-25	9555	86.61	127	1.15
2025-26*	1611	14.83	14	0.13

*स्रोत: पीएम विश्वकर्मा पोर्टल; *:14.08.2025 की स्थिति के अनुसार*

पीएम स्वनिधि योजना

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	उत्तर प्रदेश		बागपत	
	खाते	स्वीकृत राशि	खाते	स्वीकृत राशि
2020-21	5,94,316	592.86	5,777	5.76
2021-22	2,14,972	231.26	1,029	1.14
2022-23	3,52,314	569.37	2,672	4.22
2023-24	6,89,708	1,125.84	5,349	9.47
2024-25	1,55,901	334.56	1,200	2.95
2025-26*	1,249	3.32	10	0.02

*स्रोत: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय; *:14.08.2025 की स्थिति के अनुसार*

स्टैंड अप इंडिया योजना

(खातों की वास्तविक संख्या और राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	उत्तर प्रदेश		बागपत	
	खाते	स्वीकृत राशि	खाते	स्वीकृत राशि
2020-21	1,674	344.10	16	3.73
2021-22	1,347	297.28	9	2.06
2022-23	2,836	593.01	18	3.41
2023-24	4,019	875.25	11	1.48
2024-25	4,875	1,075.98	7	0.98

स्रोत: सिडबी

*****